



OK
27/3/86

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 1986/पाँच 13, 1907

No 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 1986/PAUSA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

अधिसूचनाये

सांका०नि० 14(अ) — निम्नलिखित नियम जो समद सदस्य
वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा
9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा वित्तीय मंत्रालय
से परामर्श करने के पश्चात् उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ब)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं तथा जिनका
राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा
की उपधारा (4) के अधेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है
सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं —

समद-सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम 1986

संक्षिप्त नाम और शारम्भ — (1) उन नियमों का संक्षिप्त
नाम समद सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रचलन होंगे।

2 निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ते की रकम — कोई सदस्य, समद सदस्य
वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा
8 के अधीन एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति मास की दर से
निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता पाने का हक्का होगा।

3 निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता अन्य भत्तों आदि के अनिवार्य हाना-
जफ़ाओं को दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों

के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन संबंधी भत्ता, तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य
नियमों के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं अन्य भत्तों या सुविधाओं के (चाहे वह
नकद हो या वस्तु रूप में) अनिवार्य हाना न कि उनके अन्वीकरण में।

4 निरसन—समद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) नियम, 1975
इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[फा०सं० आर एन 8/85-एम.एन.ए.]

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd January, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 14(E).—The following rules which have
been made by the Joint Committee constituted under
sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances
and Pension of Members of Parliament Act, 1954
(30 of 1954), after consultation with the Central
Government, in exercise of the powers conferred on
it by clause (f) of sub-section (3) of the said section,
and have been approved and confirmed by the Chair-
man of the Council of States and the Speaker of the
House of the People, as required by sub-section (4)
of that section, are published for general informa-
tion :—

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (CONSTITU-
TUENCY ALLOWANCE) RULES, 1986

6 हज़ार का विवाद — (1) प्रथिम ति नमय सदस्य प्रश्न ।
 में एक करार निष्पादित करेगा और खरीदारी में जोड़े पर बट पड़ित

के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आबमान करते हुए प्ररूप 2 में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा।

(2) वाहन की कीमत प्ररूप 2 में बंधपत्र के साथ सलग्न विनिर्देशों की अनुसूची में प्रविष्ट की जायेगी।

7. वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाण-पत्र—(1) जब कोई अभिम लिया गया हो, तब मंजूरी प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र भेजेगा कि अभिम लेने वाले सदस्य ने प्ररूप 1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और वह ठीक पाया गया है।

(2) मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि वाहन की खरीद अभिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित बंध पत्र को अन्तिम रूप से रिकार्ड किये जाने से पूर्व यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिये तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. बंध पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना—
(1) बंध पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(2) जब अभिम का पूर्णतः प्रतिसंदाय कर दिया गया हो, तब अभिम और उस पर व्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात्, बंधपत्र सम्यक् रद्द किया जाकर संबंधित सदस्य को वापस कर दिया जायेगा।

9. वाहन का बीमा—अभिम से खरीदे गये वाहन का अभिम, चोरी और दुर्घटना से पूरी हानि के लिये बीमा कराया जायेगा और बीमा पॉलिसी में (प्ररूप III के रूप में) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा कंपनी वाहन को ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्हीं राशियों का सदाय स्वामी के बजाय केन्द्रीय सरकार को करने के लिये करार करती है।

प्ररूप 1

(नियम 6 देखिए)

वाहन खरीदने के लिए अभिम लेने समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री _____, जो संसद सदस्य हैं (जिन्हें इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशित भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख _____ को किया गया;

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए उन नियमों के उपबन्धों के अधीन जिनमें संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अभिम मंजूर करने का विनियमन किया गया है, वाहन खरीदने के लिए _____ (_____ रूप) उधार दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम इसमें आगे दिए गए उपबन्धों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हो गई है;

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई _____ रु० (_____ रूप) की राशि (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले ने

इसके द्वारा अभिस्वीकार की है) के प्रतिकूलस्वरूप उधार लेने वाला केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह (1) उक्त नियमों के अनुसार संगणित व्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती करके करेगा, जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित है और ऐसी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है। और (2) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम वाहन खरीदने में व्यय करेगा या, यदि उसके द्वारा संसद वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो, शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त वापस कर देगा और उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम और उस पर व्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में आबमान रखने वाला दस्तावेज उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित प्रारूप में निष्पादित करेगा।

अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदा जाता है और आबमान नहीं रखा जाता है या, यदि उधार लेने वाला उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सदस्य नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर प्रोद्भूत व्याज शोध्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साथ स्वरूप उधार लेने वाले ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त श्री _____

ने उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप 2

(नियम 6 देखिए)

वाहन के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री _____

_____ (जिन्हें इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशित भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख _____ को किया गया।

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए, संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अभिम मंजूर करने से संबंधित नियमों के अनुसार (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) वाहन खरीदने के लिए _____ रु. (_____ रूप) उधार दिए जाने के लिए आवेदन किया है और उसे वह मंजूर कर दिया गया है, और उधार लेने वाले को जिन शर्तों पर अभिम दिया गया है / दिया गया था उनमें से एक शर्त यह है/थी कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आबमान रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम से या उसके भाग से वाहन खरीदा है, जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं।

यह विलेख इस बात का साक्ष्य है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसविदा करता है कि वह पूर्वोक्त _____ रु. की राशि या उसके उस अतिशेष का जो इस विलेख की तारीख को असंदत रह जाता है _____ रु. (_____ रूप) की समान किस्तों में पत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस

५१३ - महा-कुल श्रीर पद्मनाभ।

(गोपनीय के सम्बन्ध में)

की उपस्थिति में सम्मानित

उच्चारण लेने वाले का नाम और पदनाम

प्रकरण-3

(विषय 9 दिखाने)

ब मा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खर्च का प्रत्येक

यह धारणा की जाती है और करार किया जाता है कि— (वाहन का स्वामी, जिसे इनमें आने इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) न वाहन केन्द्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को उस अधिनियम के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में आबन्धन कर दिया है जो उस वाहन के खर्चाने के लिये लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार (राष्ट्रपति) ऐसे धन में हितवद्ध है जो यदि वह पुष्ठाकन न होता तो उक्त था— (इस पालिसी के अधिनियम ब.माकृत) को उक्त वाहन का हानि या उसको हुए नुकसान का बाबत (जिस हानि या नुकसान का प्रतिपूर्ति परम्परा, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) सदेव होता। ऐसा धन सरकार (राष्ट्रपति) को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह वाहन को बरकरार रहे और उसकी रमद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसा हानि या नुकसान का बाबत कर्तव्य न पूरा धार अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पुष्ठाकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जा करार किया गया है उसके विषय इसका किताब या बात से ब.माकृत के या कपनी के, इस पालिसी के अधिनियम या सबध न अधिकारी या दायित्वों का अधिनियम इस पालिसी के किताब विवेक, उपबन्ध या शर्त का न तो उपाकरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

[फा.सं.आर.एच. 8/85/एम.एच.ए.]

G.S.R. 15(E).—The following rules which have been made by the Joint Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clause (ff) of sub-section (3) of the said section, and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information :—

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (ADVANCE FOR THE PURCHASE OF CONVEYANCE) RULES, 1986.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Members of Parliament (Advance for the Purchase of Conveyance) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Maximum amount of advance.—(1) The maximum amount which may be advanced to a member for the purchase of a conveyance shall not exceed rupees twenty thousand or the actual price of the conveyance, whichever is less :

Provided that no advance shall be admissible when a conveyance has already been purchased and paid for in full :

Provided further that where such payment has been made in part, the amount of advance shall be limited to the balance to be paid as certified by the member.

(2) The amount of advance under sub-rule (1) shall be sanctioned in the name of the President and

authenticated in accordance with the provisions of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958.

3. Repayment of Advance.—(1) Recovery of the advance granted under rule 2, together with interest thereon, shall be made from the salary bill of the member concerned in not more than sixty equal monthly instalments, which shall not extend beyond the tenure of his membership :

Provided that where the member receiving the advance so desires, the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, may permit recovery of the advance to be made in lesser number of instalments.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees, except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered.

(2) The recovery of advance shall commence with the first issue of salary after the advance is drawn.

(3) Simple interest at the rate fixed by the Central Government in relation to advance for purchase of conveyance by Government servants shall be charged on the said advance.

(4) Where a member ceases to be such a member before the full repayment of the advance, the outstanding balance, together with interest thereon, shall be paid to the Central Government immediately in one lump sum.

4. Sale of conveyance.—(1) Except when a member ceases to be such a member, previous sanction of the Central Government shall be obtained for the

sale by the member of the conveyance purchased with the aid of an advance, if such advance, together with the interest accrued thereon, has not been fully repaid.

(2) Where a member wishes to transfer the said conveyance to another member, he may be permitted, under the orders of the Central Government, to transfer the liability attaching to that conveyance to the latter member provided that the member purchasing the conveyance records a declaration that he is aware that the conveyance transferred to him remains subject to the mortgage bond and that he is bound by its terms and provisions.

(3) In all cases where a conveyance is sold before the advance received for its purchase, together with interest thereon, has been fully repaid, the sale-proceeds must be applied, so far as may be necessary, towards the repayment of such outstanding balance :

Provided that when the conveyance is sold only in order that another conveyance may be purchased, the Central Government may permit the member to apply the sale proceeds towards such purchase, subject to the following conditions, namely :—

- (a) the amount outstanding shall not be permitted to exceed the cost of the new conveyance;
- (b) the amount outstanding shall continue to be repaid at the rate previously fixed, and
- (c) the new conveyance shall also be insured and mortgaged to the Central Government.

5. Period within which negotiations for purchase of conveyance may be completed.—A member who draws an advance for the purchase of a conveyance shall complete his negotiations for the purchase of, and pay finally for, the conveyance within one month of the date on which he draws the advance and finishing such completion of negotiations and final payment, the full amount of the advance drawn, together with interest thereon for one month, shall be refunded by the member to the Central Government.

6. Execution of agreement.—(1) At the time of drawing the advance, the member shall execute an agreement in Form I, and on completing the purchase, he shall further execute a mortgage bond in Form II hypothecating the conveyance to the Central Government as security for the advance.

(2) The cost price of the conveyance shall be entered in the schedule of specifications attached to the mortgage bond in Form II.

7. Certificate to the Pay and Accounts Officer.—(1) When an advance is drawn, the sanctioning authority shall furnish to the Pay and Accounts Officer of the Council of States or, as the case may be, of the House of the People, a certificate that the Agreement in Form I has been signed by the member drawing the advance and that it has been found to be in order

(2) The sanctioning authority shall see that the conveyance is purchased within one month from the date on which the advance is drawn and shall submit the mortgage bond, duly executed by the member, promptly to the Pay and Accounts Officer of the Council of States or, as the case may be, of the House of the People for examination before final record.

8. Safe custody and cancellation of mortgage bond.—(1) The mortgage bond shall be kept in the safe custody of the sanctioning authority.

(2) When the advance has been fully repaid, the bond shall be returned to the member concerned, duly cancelled, after obtaining a certificate from the Pay and Accounts Officer of the Council of States or, as the case may be, of the House of the People, as to the complete repayment of the advance and interest.

9. Insurance of conveyance.—The conveyance purchased from the advance shall be insured against full loss by fire, theft and accident and the insurance policy shall contain a clause (as in Form III) by which the insurance company agrees to pay to the Central Government instead of the owner, any sums payable in respect of loss or damage to the conveyance, which is not made good by repair, reinstatement or replacement.

FORM I

(See rule 6)

Form of agreement to be executed at the time of drawing an advance for the purchase of a conveyance

An agreement made this _____ day of _____ One thousand nine hundred and eighty _____ between Shri _____ a Member of Parliament (hereinafter called the Borrower, which expression shall include his heirs, administrators, executors, legal representatives and assignees) of the one part and the President of India (hereinafter called the Central Government) of the other Part; Whereas the Borrower has under the provisions of the Rules regulating the grant of advances to Members of Parliament for purchase of conveyance made under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 applied to the Central Government for a loan of Rs. _____ (Rupees _____ only) for the purchase of a conveyance and the Central Government have agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained;

Now it is hereby agreed between the parties hereto that in consideration of the sum of R _____ paid by the Central Government to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges), the Borrower hereby agrees with the Central Government (1) to pay to the Central Government the said amount with interest calculated according to the said rules by monthly deductions from his salary as provided for by the said rules and hereby authorises the Central Government to make such

deductions and (2) to expend, within one month from the date of these presents, the full amount of the said loan in the purchase of a conveyance or if the actual price paid is less than the loan, to repay the difference to the Central Government forthwith and to execute a document hypothecating the said conveyance to the Central Government as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest thereon in the form provided by the said rules; And it is hereby Lastly agreed and declared that if the conveyance has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or ceases to be a member or dies, the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall become due and payable.

In witness whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written

Signed by the said Shri
in the presence of

FORM II

(See rule 6)

FORM OF MORTGAGE BOND FOR CONVEYANCE

THIS INDENTURE made this _____ day of _____ one thousand nine hundred and Eighty _____ BETWEEN _____ (hereinafter called "the Borrower", which expression shall include his heirs, administrators, executors, legal representatives and assignees) of the one part and the President of India (hereinafter called, the Central Government) of the other part; WHEREAS the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rupees, _____ to purchase a conveyance in terms of Rules regarding the grant of advances to Members of Parliament for the purchase of conveyance made under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (hereinafter referred to as "the said Rules") AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said conveyance to the Central Government as security for the amount lent to the Borrower and WHEREAS the Borrower has purchased with, or partly with, the amount so advanced as aforesaid the conveyance particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Central Government the sum of Rs. _____ aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payment of Rs. _____ each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing, calculated according to the said Rules and the Borrower doth agree that such

payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer unto the Central Government the conveyance the particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said Rules.

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said conveyance and that the same is his absolute property and that he has not pledged and, so long as any money remains payable to the Central Government in respect of the said advance, will not sell, pledge or part with the property in, or possession of, the said conveyance. Provided always and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time ceases to be a Member or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in, or possession of, the said conveyance or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower, the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid, together with interest thereon, calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the Central Government may on the happening of any of the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said conveyance and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said conveyance either by public auction or private contract and may out of the sale money retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realizing its rights hereunder and shall pay over the surplus, if any to the Borrower his executors, administrators or personal representatives : PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of said conveyance shall not prejudice the right of the Central Government to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the conveyance being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing; AND the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Central Government, he, the Borrower will insure and keep insured the said conveyance against loss or damage by fire, theft, and accident with an Insurance Company to be approved by the Accountant General concerned and will produce evidence to the satisfaction of the Accountant General that the Motor Insurance Company with whom the said motor vehicle is insured have received notice that the Central Government (President of India) is interested in the Policy

thereof and further that in the event of any damage or accident happening to the said conveyance the Borrower will forthwith have the same repaired and made good

Description of Conveyance
Maker's name
Description
No. of cylinders
Engine Number
Chassis No.
Cost Price

IN WITNESS Whereof the said _____ (Buyer's Name) and
 behalf of the President of said have hereunto set their respective hands, this day and year first above written.

Signed by the said
in the presence of

1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
2	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

(Signature of Witnesses)

(Signatures and Designation of the Witnesses)

Signed by (name and designation)

for an on behalf of the President of India
in the presence of

1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____

(Signatures of Witnesses)

(Signatures and Designation of the Officer

Name and designation of the Borrower

(See rule 9)

Form of the clause to be inserted in Insurance Policies

1 It is hereby declared and agreed that Shri _____ (the owner of the conveyance hereinafter referred to as the insured in the Schedule to this policy) has hypothecated the conveyance to the Central Government (President of India) as security for advance for the purchase of the conveyance and it is further declared and agreed that the said Government (President) are interested in any moneys which but for this endorsement be payable to the said Shri _____ (the insured under this policy) in respect of the loss or damage to the said conveyance (which loss or damage is not recoverable by repair, reinstatement or replacement) and such moneys shall be paid to the said Government (President) as long as they are the mortgagees of the conveyance and their receipt shall be full and final discharge to the Company in respect of such loss or damage.

2. ² Sav as by this endorsement it expressly agree, nothing herein shall modify or affect the rights or liabilities of the insured or the company respectively under or in connection with this policy or any term, provision or condition thereof

[F No RS 8 85/MSA]

मा का नि 16 (अ)---निम्नलिखित नियम जो मसद सदस्य
बेसन भत्ता आर पेशन इग्नियस 1954 (1954 का 31) की धारा
9 की धारा (1) र मयन गति सयका समिति द्वारा कन्द्रीय सरकार
से परामर्श करने के पश्चात् उक्त धारा क उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं तथा जिनका राज्य न्याय के
सभापति वार लोक न्याय के अध्यक्ष द्वारा वर धारा का उपधारा
(4) की श्रपेक्षातुसार यन्भावन आर पुष्टि कर र गए हैं नवम्बरवारण
की जानकारी के लिए आकाशित किए जाते हैं।

प्रा. और टर्नेपान मरिगा

(समाप्त) लक्षात्त नियम १७ ७

1. नक्षिण नाम और प्रारम्भ - (1) इस विचार की जिज्ञा
नाम अर्वाच्य और वेदकाल युक्ति (संस्कृत) नाम 'म' 1986 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवाहन और टेलीफोन सुविधा (मसद सदस्य) निम्न ११००
(जिन्हें हमके पत्रवात् उक्त नियम कहा गया है) में निम्न में स्थान
पर निम्नलिखित नियम छ जायगा अर्थात् —

“2 सदस्या का वाणिज्य आदि की सुविधा । अथवा
सदस्य अपने पूरे कार्याकांक्षित रूप में निर्यात आयात विधा
का हकदार होगा

परन्तु यह कि जहाँ तदर्थ का उनके अनुपाय पर तो है नही है
वाम-सुविधा शरित की जाये वहाँ वह -

(क) पूरा सामान्य किसानों को मदद करेगा यदि वह
या हकदार है, और

(ख) पूर्ण सामान्य किराया और पांच सौ रुपए प्रतिमास गैर-हकदारों द्वारा सदन करेगा। यदि वह इसका हकदार नहीं है।”

स्पष्टीकरण (1) —उन उप-नियम के प्रयोजनों के लिए “फ्लैट” के अंतर्गत होस्टल वाम सुविधा है।

(2) प्रत्येक सदस्य, उप-नियम (1) के अधीन उसे आबंटित किसी वाम-सुविधा के संबंध में, प्रति मास तीन सौ रुपए से अधिक तक की राशि के पाने और बिजली की निशुल्क प्रदाय का भी हकदार होगा।

(3) जहां, उप-नियम (1) में निदिष्ट किसी वाम-सुविधा के संबंध में, हमने किए गए किसी मुद्यार या वृद्धि के कारण अथवा इसमें उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के कारण किराया देय हो, वहां इस प्रकार के मुद्यार, वृद्धि या अतिरिक्त सेवा के संबंध में किराए की राशि देय सामान्य किराए से 25% कम होगी।

स्पष्टीकरण 1:—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए “मुद्यार या वृद्धि” से अतिरिक्त वाम-सुविधा, फर्नीचर, टेबल और पैडस्टल पखो, टेबल लैम्पो, लॉरे स्टैण्ड लैम्पो, बायलरो, प्रशानकर्म, डेजेटक्यूरो और वानानुकूलन यूनितों की व्यवस्था अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 —“फर्नीचर” से फर्नीचर की ऐसी मदे अभिप्रेत है, जो किसी सदस्य का उसे आबंटित निवास-स्थान के लिए मिलनी है और इस के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा अपने निवास-स्थान में किराए पर ली गई अतिरिक्त मदे भी है।

स्पष्टीकरण 3 —“अतिरिक्त सेवा” से अभिप्रेत है,—

(क) सदस्यों के निवास-स्थानों में सबड हाडूकशो, जमादारों तथा कर्मचारियों का डाइन और डाडू उपलब्ध करना;

(ख) सदस्यों को वाम-सुविधाओं पर विजली के बल्बों का प्रदाय।

(ग) फ्लो का क्यारियों का रख रखाव।

(घ) सदस्यों के फायदे के लिए बनाए गए किसी स्थान (जैसे पूछताछ कार्यालय) का रख-रखाव, और

(ङ) सदस्यों के फायदे के लिए उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सुविधा।

3. उक्त नियमों के नियम 2क में “किराए का उमी दर पर जो सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके द्वारा संदेय था” शब्दों के स्थान पर “उन्हीं निबंधनों पर जो सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे लागू थे” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में,—

(क) उप-नियम (1) में

“सात हजार पांच सौ” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह हजार” शब्द रखे जाएंगे,

(ख) उप-नियम (3) में “सात हजार पांच सौ” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह हजार” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 4क में —

(क) उप-नियम (1) में

“पन्द्रह हजार” शब्दों के स्थान पर “तीस हजार” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) में “तीन हजार सात सौ पचास” और “सात हजार पांच सौ” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पांच सौ” और “पन्द्रह हजार” शब्द रखे जाएंगे,

(ग) उप-नियम (3) में “सात हजार पांच सौ” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह हजार” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा:—

“(4) सदस्यों के दूक काल बिल उपरोक्त तीस हजार पांच प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के धनीय समतुल्य के अंतर्गत समायोजित किए जा सकेंगे।”

6. उक्त नियमों के नियम 5 के पश्चात् में “उसके द्वारा अधिभोग किया जाता है” शब्दों के पश्चात् “एक निवास-स्थान के लिए” शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

[फा.स. आर.एस 8/85-एम.एस.ए.]

मन्देशन अग्रवाल, महा सचिव

G.S.R. 16(E).—The following rules, which have been made by the Joint Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clause (f) of sub-section (3) of the said section, and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information:—

THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) AMENDMENT RULES, 1986

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“2. Facilities of housing etc. to Members.—(1) Each members shall be entitled without payment of rent to housing accommodation in the form of a flat throughout his term of office:

Provided that where a member is allotted housing accommodation in the form of a bungalow at his request, he shall pay—

(a) full normal rent if he is entitled to such accommodation; and

(b) full normal rent and a non-entitlement charge of rupees, five hundred per mensem, if he is not so entitled.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule “flat” includes hostel accommodation.

(2) Every member shall, in respect of any accommodation allotted to him under sub-rule (1), also be entitled without payment of charges to the supply of water and electricity upto an amount not exceeding rupees three hundred per mensem.

(3) Where in respect of any accommodation referred to in sub-rule (1), rent is payable on account of any improvement or addition made to it or any additional service provided thereto, it shall be twenty-five per cent less than the normal rent payable in respect of such improvement, addition or additional service.

Explanation I.—For the purposes of this sub-rule “improvement or addition” means the provision of additional accommodation, furniture, table and pedestal fans, table lamps, floor standard lamps, boilers, refrigerators, desert coolers and air-conditioning units.

Explanation II.—“Furniture” means such items of furniture as are admissible to a member for a residence allotted to him and includes any additional items taken on rent by a member in his residence.

Explanation III.—“Additional service” means,

- (a) the provision of Sweepers, Jamadars and the staff attached to members' residences with dusters and brooms;
 - (b) the supply of electric bulbs at the residences of members;
 - (c) the maintenance of flower beds;
 - (d) the maintenance of any place (like an Enquiry Office) intended for the common benefit of members; and
- any other service provided for the common benefit of members.”

3. In rule 2A of the said rules, for the words “same rate of rent as was payable by”, the words “same terms as were applicable to” shall be substituted.

4. In rule 4 of the said rules,—

- (a) in sub-rule (1), for the words “seven thousand five hundred”, the words “fifteen thousand” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (3), for the words “seven thousand five hundred”, the words “fifteen thousand” shall be substituted.

5. In rule 4A of the said rules,—

- (a) in sub-rule (1), for the words “fifteen thousand”, the words “thirty thousand” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words “three thousand seven hundred fifty” and “seven thousand five hundred”, the words “seven thousand five hundred” and “fifteen thousand” shall, respectively, be substituted;
 - (c) in sub-rule (3), for the words “seven thousand five hundred”, the words “fifteen thousand” shall be substituted;
 - (d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
- “(4) The trunk call bills of the members may be adjusted within the monetary equivalent of the ceiling of thirty thousand local calls per annum as aforesaid”.

6. In rule 5 of the said rules, in the proviso, after the words “of rent” the words “for one of the residences” shall be inserted.

[F. No. RS 8/85 MSA]
SUDARSHAN AGARWAL,
Secretary-General.